

## अनुसूचति जनजाति (ST) सूची में संशोधन हेतु वधियक

### प्रलमिस के लयि:

राष्ट्रीय अनुसूचति जनजाति आयोग, अनुसूचति जनजाति, संवधान की पाँचवी अनुसूची, संवधान की छठी अनुसूची ।

### मेन्स के लयि:

अनुसूचति जनजातियों की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया, भारत में जनजातियों से संबंधति संवधानिक प्रावधान और पहल ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में 4 राज्यों - तमलिनाडु, कर्नाटक, हमिचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में [अनुसूचति जनजाति \(ST\) सूची](#) को संशोधति करने की मांग करने वाले चार वधियकों को [संवधान \(ST\) आदेश, 1950](#) में प्रस्तावति संशोधनों के माध्यम से [लोकसभा](#) में पेश कयि गया था ।

## प्रस्तावति परिवर्तन:

- वधियक का उद्देश्य:
  - तमलिनाडु की ST सूची में [नारीकोरवन और कुरुवकिकरन पहाड़ी जनजातियों](#) को शामिल करना ।
    - [लोकसमति \(1965\)](#) ने भी अपनी रिपोर्ट में उन्हें सूची में शामिल करने की सफिरशि की थी ।
  - कर्नाटक की ST सूची में पहले से ही वर्गीकृत [काडू कुरुबा](#) के पर्याय के रूप में [बेटटा-कुरुबा](#) को शामिल करना ।
  - छत्तीसगढ़ की ST सूची में पहले से वर्गीकृत भारयि भूमयि जनजाति के लयि देवनागरी लिपि में अन्य समानार्थक शब्द जोड़ना ।
    - जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, वे सभी एक ही जनजाति का हसिसा हैं, लेकिन उन्हें सूची से बाहर रखा गया था क्योंकि उनके नाम अलग-अलग हैं ।
  - सरिमोर ज़िले में ट्रांस-गरि क्षेत्र के [हट्टी समुदाय](#) को हमिचल प्रदेश की ST सूची में शामिल करना (लगभग पाँच दशकों के बाद) ।

## ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया:

- राज्य द्वारा सफिरशि:
  - जनजातियों को ST की सूची में शामिल करने की प्रक्रया संबंधति राज्य सरकारों की सफिरशि से शुरू होती है, जसि बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लयि [भारत के महापंजीयक](#) को इसे प्रेषति करता है ।
- NCST से मंजूरी: इसके बाद सूची को अंतिम नरिणय के लयि कैबिनेट को भेजे जाने से पहले [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजाति आयोग \(National Commission for Scheduled Tribes- NCST\)](#) द्वारा मंजूरी दी जाती है ।
- राष्ट्रपति की सहमति: अंतिम नरिणय करने की शक्ति राष्ट्रपति में नहिति है ([अनुच्छेद 342](#) के तहत) ।
  - अनुसूचति जनजाति में कसि भी समुदाय को शामिल करने की प्रक्रया संवधान (अनुसूचति जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले वधियक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होती है ।

## भारत में अनुसूचति जनजातियों से संबंधति प्रावधान

- परभाषा:
  - भारत का संवधान अनुसूचति जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परभाषति नहीं करता है । [वर्ष 1931 की जनगणना](#) के अनुसार, अनुसूचति जनजातियों को "बहषिकृत" और "आशकि रूप से बहषिकृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पछिड़ी जनजातियों" के रूप में मान्यता जाना जाता है ।
  - भारत सरकार अधिनयिम 1935 ने पहली बार प्रांतीय वधिनसभाओं में "पछिड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों को शामिल कयि जाने की मांग की ।
- संवधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 366 (25): इसमें अनुसूचित जनजातियों को "ऐसी आदवासी जातियाँ आदवासी समुदाय या इन आदवासी जातियों और आदवासी समुदायों के भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिये अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है" परभाषित किया है।
- अनुच्छेद 342(1): राष्ट्रपति किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में (राज्य के मामले में राज्यपाल के परामर्श के बाद) उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जनजातियों/जनजातीय समुदायों/जनजातियों/जनजातीय समुदायों के कुछ भागों या समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में वनिरिदषित कर सकता है।
- पाँचवी अनुसूची: यह 6वी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान नरिधारित करती है।
- छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
- वैधानिक प्रावधान:
  - असप्रशयता के वरिदुध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
  - अनुसूचित जातों और अनुसूचित जनजातों (अत्याचार नवारण) अधिनियम, 1989
  - पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक वसितार) अधिनियम (पेसा), 1996
  - अनुसूचित जनजातों और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

**?????????:**

प्र. यदि किसी वशिषित क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो नमिनलखित कथनों में कौन-सा एक कथन इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? (2022)

- इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर-जनजातीय लोगों के अंतरत कराने पर रोक लगेगी।
- इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी नकाय का सृजन होगा।
- इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा।
- जसि राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे, उसे वशिष कोटिका राज्य घोषित किया जाएगा क्षेत्रों वाले राज्य को वशिष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा।

उत्तर: (a)

प्र. भारत के संविधान की कसि अनुसूची के तहत खनन के लिये नजी पारटियों को आदवासी भूमिके हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019)

- तीसरी अनुसूची
- पाँचवी अनुसूची
- नौवी अनुसूची
- बारहवी अनुसूची

उत्तर: (B)

**?????????:**

प्र. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रतभेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिक पहलें क्या हैं? (2017)

**स्रोत: द हट्टि**